International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9 Issue 5, May 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

फिर मोदी सरकार: आर्थिक नीति को जनता की स्वीकृति!

डॉ उमेश प्रताप सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर,अर्थशास्त्र विभाग
इविंग क्रिश्चियन कालेज
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

सार
मोदी सरकार का दुबारा चुना जाना इस बात की मिसाल है कि सरकार ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ और फोकस होकर बेहतर प्रशासन और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किया है। शौचालय , बिजली, बैंक के अकाउंट, रसोई गैस, गरीबों के बैंक खाते तक सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण आदि महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि आम व्यक्ति से मोदी को सीधे जोड़ते हैं और अंततः गरीबो, पीड़ित, शोषित लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाने में हम भूमिका निभाई। पहले 5 वर्षों में मोदी सरकार में कुछ बेहद साहस भरे सुधार लागू किए। सरकार ने उधार की वास्तविक लागत को कम किया, आय व निवेश पर करों को मामूली बढ़ाया और वस्तुओं पर जीएसटी में, कर में कमी की, सबसे महत्वपूर्ण था जन सुविधाओं का विस्तार, बिजली उत्पादन, शौचालय, सड़क , बैंक खाते, शिक्षा इन सभी की पहुंच गरीबों तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी।पहली बार एक ऐसा चुनाव लड़ा गया है जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, जोकि एक बेहद महत्वपूर्ण बात है।

महत्वपूर्णशब्द: बेहतर प्रशासन, आर्थिक सुधार, सरकारी योजनायें, महंगाई, निवेश

अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में आश्चर्यजनक रूप से सफल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मोदी ने कहीकि हमें गरीबों ने जिताया है, उन्होंने फिर से अपनी सरकार बनाई है। स्पष्ट है कि जिस महात्मा गांधी के रास्ते का मोदी ने जिक्र किया, उसपर चलकर सरकार ने दिखाया भी, इस सरकार ने गाँधी के सिद्धांतों पर अमल भी किया और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख कर के अपनी योजनाएं बनाईं। सारी धर्म और जाति के दीवारों को तोड़ते हुए गरीबों, महिलाओं और शोषितों ने एक बार फिर से मोदी की सरकार बनवाई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कही गई यह बात उनकी योजनाओं में दिखती है, उनकी योजनाओं में समाज के उस अंतिम व्यक्ति के आंसू पोछने का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है।

गरीबोंऔरउपेक्षितोंकीसरकार

जनधन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, जन औषधि योजना, **अटल पेंशन योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप इंडिया स्टेंड अप इंडिया जैसी अनेक योजनायें मोदी सरकार ने शुरू की जिनका फायदा समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित वर्ग को मिला।** भारत में पहली बार इस सरकार औपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना जैसी कोई महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. xIssue x, Month 201x,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सरकार ने एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2018 में शुरू की थी और 2019 में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी 2019 तक इस योजना से 10 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहतसरकार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आने वाले परिवारों को रु 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। 10 करोड़ बीपीएल परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ देने के बादइसमें शेष भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा।

उज्जवला योजना के तहत बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उसे मोदी सरकार ने प्रेरित किया कि वे उस सब्सिडी को छोड़ें, जिससे गरीब लोगों को सब्सिडी दिया जा सके और लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ा, 7 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ।

किसानो की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने और कृषि उत्पादों की कीमतें दुगुनी करने के साथ ही सरकार ने सभी लघु और सीमांत किसानों को, प्रतिवर्ष □6000 देने का भी प्रावधान किया। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाये गये।

भ्रष्टाचारपरकरारापहारयानिगरीबोंकीअधिकमदद

भ्रष्टाचार को कम या समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने अनेक बेहद साहसी और जोखिम भरे कदम उठाये। बिना अपने वोट बैंक का ख्याल किये, सुशासन को सुनिश्चित कर गरीबों तक उनकी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचे, सिर्फ इस ध्येय से ही योजनायें बनायीं और लागू की गयीं। नोटबंदी भी इसी उद्देश्य से उठाया गया साहसिक कदम था। और जीएसटी ने भी भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत अब तक 2.8 लाख करोड़ से अधिक रूपया प्रत्यक्ष तौर पर लोगों के खाते में हस्तांतरित हुआ है। इससे मनरेगा और एल पी जी सब्सिडी के तहत जो भ्रष्टाचार होता था उस पर रोक लगी है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 4 वर्षों में 1.2 लाख करोड़ रुपए इस प्रकार के रिसाव और भ्रष्टाचार से बचाया जा सका है। यही नहीं विभिन्न योजनाओं से 7 करोड़ से अधिक फर्जी खातों को समाप्त करने में मदद मिली। स्पष्ट है कि इस बचे हुए पैसे को कल्याणकारी योजनाओं में सरकार लगाएगी और साथ ही वास्तविक लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है।

इनसॉल्वेंसीएंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) यानी दिवाला कानून बहुत बड़ा सुधार है।भारत में अब भ्रष्टमालिकों से बुरे ढंग से चलाई जाने वाली कंपनियों को छीनाजा सकता है। इसके तहत 2018 तक कुल 3 लाख करोड़ की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) की वसूली जा चुकी है, सरकार अब तक 66 केस में 80 हजार करोड़ रूपया की वसूली की है, 4452 केसों में प्रारंभिक स्तर पर ही समायोजन करने में मदद मिली और उसके समायोजन के द्वारा बैंकों को दो लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए।

गरीबोंकेलिएबेहदजोखिमभरेनिर्णय

जब सामने अंतिम व्यक्ति का चेहरा हो तो फिर उनके हित के लिए ईश्वर जोखिम लेने का भी हौसला दे ही देता है। नोटबंदी करके मोदी सरकार ने सबसे बड़ा जोखिम लिया था। खराब बात यह थी कि बिना ठोस तैयारी के यह कदम उठाया पड़ा था। इससे लोगों को दिक्कतें जरूर हुई, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र पर बड़ी मार पड़ी, नौकरियां भी इस क्षेत्र में कुछ समय के लिए चली गई, परंतु दीर्घकाल में इसका फायदा दिख रहा है और इससे अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण में मदद मिल रही है।

परंतु नोटबंदी के बाद भी सरकार भाजपा की ही बनी उत्तर प्रदेश में! जोकि स्पष्ट संकेत था कि गरीब तबका अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहता है। नोटबंदी ने भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारीओं के मन में एक भय तो व्याप्त किया ही। हालांकि उसभय को कम करने और नोटबंदी के असर को कम करने में सरकार के ही अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने काफी मदद की, परंतु कर देने वालों की संख्या में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. xIssue x, Month 201x,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

दुगने से अधिक वृद्धि, साढ़े तीन लाख से अधिक फर्जी कंपनियों का पकड़ा जाना, काले धन का बड़ी मात्रा में पकड़ा जाना इत्यादि ऐसे तमाम सूचक है, जो कि इस बात का संकेत है कि नोटबंदी के परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बेहतरी में इसका लाभ लम्बे समय बाद धीरे धीरे अब समझ में आ रहा है।

दूसरा ऐतिहासिक और साहसिक कदम था जीएसटी का लागू किया जाना। यह जानते हुए कि यह एक ऐसा कदम है जो सरकार की चूलें हिला सकता है, व्यापारियों के एक बहुत बड़े तबके को नाराज कर सकता है, जो कि भाजपा का एक प्रमुख वोट बैंक है; इतिहास भी सामने था कि अब तक जिन भी देशों में, जिन भी सरकारों ने जीएसटी को लागू किया है उनकी सरकार दुबारा चुनकर के नहीं आई है , फिर भी मोदी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई और जोखिम लिया।अब जीएसटी के भी सार्थक परिणाम दिखने लगे हैं। बहुत सारे संशोधन किए जाने के बाद यह सच में काफी सरल हो गया है। यह प्रक्रिया अभी जारी है और कर संग्रहण में भी लगातार वृद्धि हो रही है। व्यापारी भी अब इसे लेकर धीरे-धीरे सहज होता जा रहा है।अधिकांश वस्तुओं पर कर के भार में कमी आई है। अधिकतर आम उपभोग की वस्तुओं पर यह कमी 4प्रतिशततक थी और कुछ वस्तुओं में यह 15प्रतिशततक थी। स्पष्ट है कि जीएसटी से आम उपयोग वस्तुएं सस्ती हुई। इसीलिए यह ऐसी पहली सरकार है जो कि जीएसटी लागू करने के बाद भी सत्ता में वापस आई। अभी जब जीएसटी का दायरा बढ़ेगा तो इन वस्तुओं पर कर के भार में और कमी आएगी।

कीमतोंपरनियंत्रणकेजरियेगरीबोंकोराहत

प्रधानमंत्री मोदी की यह बात सौ प्रतिशत सच है कि पहली बार चुनाव में महंगाई एक मुद्दे के रूप में नहीं रहा, वरना बढ़ती हुई कीमतें चुनावी दांव पलटने के लिए हमेशा से जिम्मेदार रही हैं। परंतु मोदी सरकार के दौरान कीमते बेहद नियंत्रित रही है।मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में मुद्रास्फीति को सुरक्षित सीमा के भीतर ही नियंत्रित रखा, मुद्रास्फीति के निम्न और स्थिर रहने और साथ ही राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के कारण आरबीआई को ब्याज दर की कटौती करनी पड़ी और वह लगभग 1प्रतिशत बिंदु तक ब्याज दरों में कटौती कर पाया और उधार की वास्तविक लागत को कम किया। आयकर के आधार पर यदि देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा फायदा निम्न मध्यवर्ग को हुआ , 20 लाख तक की आय वालों को यह फायदा लगभग 7प्रतिशततक था। जबकि धनी व्यक्तियों पर आयकर का भार 3 से लेकर के 9प्रतिशततक बढ़ा है। ।

निवेशऔरसंवृद्धिकोबढ़ानेकेप्रयास

पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने विकास को बेहतर बनाए रखा है बल्कि अन्य आर्थिक संकेतकों को भी नियंत्रण में रखा है, राजकोषीय घाटा, सब्सिडी, कीमत वृद्धि की दर, सभी एक सीमा के भीतर ही रहे हैं और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।

सरकार नेराज्य के हस्तक्षेप को कम करने के लिए भी अनेक कदम उठाए, इसके तहतबड़े , छोटे, मझोले और सूक्ष्म सुधारों सहित कुल 7,000 उपाय (सुधार) किए गएहैं। जिससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में छलांग लगाते हुए भारत2014 के 134वें स्थान से 2019 में 77वें स्थान पर पहुंच गया।2014 से 2019 के बीच में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनी।भारत में निवेश का उचित माहौल बनाने के लिए नियमों और कानूनों में संशोधन के साथ साथ आधारिक संरचना में भी बेहतरी की आवश्यकता थी और सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। विमुद्रीकरण या नोटबंदी के बाद भी नीति आयोग का कहना है कि यूपीए की अपेक्षा एनडीए सरकार में आर्थिक समृद्धि की दर ज्यादा रही है, यह यूपीए सरकार के पिछले 5 वर्षों में 7प्रतिशत के मुकाबले

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. xIssue x, Month 201x,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

एनडीए सरकार में 7.6प्रतिशत रही है। 2018 में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए विश्व की छठी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया, 2000 से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा 1.5प्रतिशत से 3.2प्रतिशत हो गया है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बढ़कर अब $2000 हो गया है जो कि 10 वर्ष पहले की अपेक्षा 2 गुना है।

आधारिकसंरचनातकगरीबोंकीपहुँचबढ़ी

आधारिक संरचना में निवेश में भी मोदी सरकार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह 2014 की अपेक्षा लगभग 3 गुना हो गया है , जिससे की सड़क और रेल जैसी यातायात सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मोदी सरकार ने प्रतिदिन लगभग 30 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जो कि यूपीए द्वितीय की दर से दोगुनी से अधिक है। 2009-10 में कुल हाईवे कंस्ट्रक्शन 5146 किलोमीटर था, जोकि बढ़कर 2018-19 में 11000 किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार, 2018-19 में वार्षिक विमान यात्रियों की संख्या 35 करोड़ पार कर गई, जो कि 10 साल पहले की संख्या से 3 गुना से भी ज्यादा है, ऐसा विमान किराए में स्थिरता और एयरपोर्ट के विस्तार के कारण संभव हो पाया।

सामाजिक सूचकांकों में भी मोदी सरकार ने बेहतर कार्य किए और विशेष रूप से शौचालय की पहुंच जो कि 2014 में 38प्रतिशतजनसंख्या तक थी उसे बढ़ाकर लगभग 100प्रतिशतकर दिया। मोदी के 5 वर्षों के दौरान फोन घनत्व और इंटरनेट पहुंच में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 2009 में जहां प्रति व्यक्ति 40 लोगों के पास और 2013 में 73.5 लोगों के पास फोन था वहीं 2018 में बढ़कर यह 91 से अधिक हो गया।वहीं, जिओ के आने के बाद , सस्ते डाटा के कारण इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की संख्या मार्च 2014 के 25.2 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2018 में 46 करोड़ हो गई और इस बीच डाटा उपयोग प्रति सबस्काईबर 147 एमबीसे बढ़कर 2437 एमबी या 2.4 जीबी हो गया।

2019, नयीचुनौतियाँ!

मोदी सरकार ने रिकॉर्ड बहुमत पाते हुए एक बार फिर सरकार बना ली है। पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार संभालते वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मंदी की स्थिति अभी भी बनी हुई है और यह अभी भी अपने निचले स्तर पर नहीं पहुंची है। पिछले तीन तिमाही से भारतीय अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, संवृद्धि दर 6प्रतिशत रह गई है। ज्यादातर आर्थिक संकेतक यही बताते हैं कि अभी भी अर्थव्यवस्था भविष्य में और नीचे की ओर जाने का संकेत दे रही है, कम से कम ऊपर जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में रोजगार की स्थिति और बुरी हो सकती है, 2018 में बेरोजगारी दर 45 वर्षों में 2016- 17 के बीच सबसे अधिक रही है। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं ।ऐसे में मोदी सरकार से यह उम्मीद है कि वह इसे गति प्रदान करें और अर्थव्यवस्था को और नीचे जाने से बचाए।

ऐसे में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार को अपने निवेश कार्यक्रमों को गति देनी होगी और विशेष रूप से मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और ऐसे समय में जबकि मंदी की आहट हो, सारे संकेतक नीचे की ओर हों, निजी निवेश को बढ़ाना आसान नहीं है।

वास्तव में पिछले 15 वर्षों में भारत की समृद्धि में घरेलू मांग का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति नहीं आई और यह विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। लेकिन अब यह जरूरी हो गया है कि सरकार निवेश को बढ़ाने के लिए अब निर्यात पर गंभीरता से ध्यान दें क्योंकि बिना निर्यात बढेविनिर्माण क्षेत्र में तेजी की संभावना कम है। इस समयअर्थव्यवस्था के विकास की असली चाबी निर्यात वृद्धि है।

References:

1. Sardesai, Rajdeep (2019): How Modi Won India; Harper India
2. Economic Survey 2017-18; Government of India; Ministry of Finance, New Delhi; January 2018
3. Economic Survey 2016-17; Government of India; Ministry of Finance, New Delhi; January 2017
4. Dutta,Prabhash K (2019): Election results 2019: 5 reasons that got NarendraModi another term, May 23, 2019 https://www|indiatoday|in/elections/lok-sabha-2019/story/election-results-2019-5-reasons-that-got-narendra-modi-another-term-1532978-2019-05-23
5. Kumar, Shakti Shekhar (2019):10 reasons why NarendraModi-led BJP won LokSabha elections ; TIMESOFINDIA|COM,May 23, 2019
   http://timesofindia|indiatimes|com/articleshow/69466610|cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
6. Joseph, Tony (2019): How NarendraModi's mandate for 2019 is different from the one in 2014;TIMESOFINDIA|COM, May 24, 2019
7. Surjit S Bhalla (2017):This election was about past record of Modi government and expected performance; May 25, 2019
   https://indianexpress|com/article/opinion/columns/narendra-modi-bjp-lok-sabha-election-results-congress-rahul-gandhi-5747308/